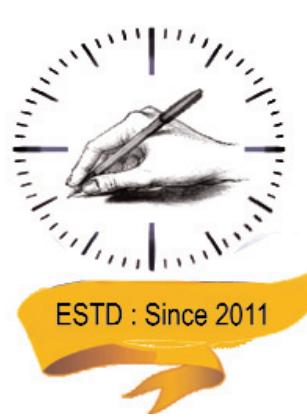




राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

# समय



रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

# दर्शन

संस्थापक : स. श्रीमति निलिमा खड़तकर

निष्क्रियनिर्भक खबरों के साथ

दुर्ग, गुरुवार 28 नवम्बर 2024

www.samaydarshan.in

वर्ष 14, अंक 41

पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

मुझे सीएम बनने की लालसा नहीं

## पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला मंजूर-शिंदे

मुंबई/ एजेंसी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं का विराम दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होंगे। साकार बनाने समय मेरी तरफ से कोई अड़बन नहीं आएगी। मैं चंद्रगढ़ की दोरी से पहुंचती है। रेलवे को कोहरे के चलते कई ट्रेनों को हर दिन तमाम ट्रेनों को कैरेसिल करना पड़ता है। यही नहीं निलिमा खड़तकर का सचालन होता वह ट्रेनों भी अपने गतव्य तक कई-कई घंटों की दोरी से पहुंचती है। रेलवे को कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रह करना पड़ा है। यही नहीं रेलवे ने आज कई ट्रेनों के संचालन के समय में भी बदलाव किया है। जबकि भूले ट्रेनों को दूसरे रुट पर दायर किया गया है। अमित शाह और पीएम



दिक्त आती है, मैं समझता हूं। मैंने खुद को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने आम आदमी की तरह काम किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं है, तो पीएम मोदी और अमित शाह अपने में कोई संदेश न दिख रहा है। हमने लाडली बहन योजना पर काम शुरू किया। मैं लाडली बहनों का लाडला भाई हूं। उन्होंने कहा कि आगर मेरी वजह से अमादवादी की धोषणा में देरी की एक बड़ा कारण है। इंटीमैन-बैलेट पेरप मुंबई पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़े ने धोषणा की है कि हम बैलेट पेरप से मतदान बहाल करने के लिए अपनी आवाज उठाएंगे।

कुछ दिन पहले ही आप छोड़ बीजेपी में हुए शामिल

## कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली/ एजेंसी



भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक हफ्ते से अधिक समय बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व बेटा और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एकांकी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास विधायकों हवाला देते हुए जोगत को भेजा। 17 नवंबर को कैलाशवाल पर भी कटाक्ष किया गया। उन्होंने एकांकी के लोगों से विश्वास करते हुए अपने फैसले को सदेह होता है कि क्या हम का कारण बताते हुए उन्होंने अपनी भी 'आम आदमी' होने में शामिल होने के बाद जीवंत की गयी। उन्होंने कहा कि कहि पार्टी दिल्ली के लोगों से विश्वास करते हुए किसी भी गहलोत ने कहा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह फैसला रातोंतांत्र और किसी के दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अन्दर बहुत कमी किसी के दबाव में उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने अपने आज तक कभी किसी के दबाव में कुछ नहीं किया। मैं सुन रहा हूं कि एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह ईडी और सीवीआई के दबाव में विफलता लोगों के प्रति पार्टी की क्षिलाफ भी बात की जाए। इसके बाद राजीनीतिक महत्वाकांक्षानं नदी को साफ करने में विफलता लोगों के बाद अपने निवेश जारी कर कक्षा 12 तक की सभी कक्षाओं को भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरह से चलाने का निर्देश दिया है।

## वीरांगना झलकारी बाई का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया

नई दिल्ली/ एजेंसी



अखिल भारतीय कोली/कोरी समाज के तत्वाधान में वीरांगना झलकारी बाई का 194 जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने कहा कि दिल्ली में 1993 से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दू लेकिन आजतक भाजपा ने कोली समाज के किसी भी व्यक्ति को विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया है। 2015 में आप ने कोली समाज के धमेंद्र कोली की अपना प्रत्याशी बनाया था और वो चुनाव जीतकर आए। कोली समाज के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में कोली समाज के राष्ट्रीय कोली को लालसा नहीं करते हैं।

कोली समाज के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में कोली आदमी 18 से 20 लाख हैं

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीता 2 इलाकों में एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग बुझाने के बाद अंदर चालते अपरेशन चलाया गया। इस दौरान यहीं चाल चली अंदर गंभीर हालत में मिले। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और आग लगने के दौरान यहां मौजूद थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 नवंबर को थाना बीता 2 थंक्रे के अंतर्गत साइट फॉर एंट्री नंबर 4 जी में आग लग गई। यहां सोफा बनाने का काम होता है। आग लगने की सूचना पर तकाल स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीता 2 इलाकों में एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग बुझाने के बाद अंदर चालते अपरेशन चलाया गया। इस दौरान यहीं चाल चली अंदर गंभीर हालत में मिले। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और आग लगने के दौरान यहां मौजूद थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 नवंबर को थाना बीता 2 थंक्रे के अंतर्गत साइट फॉर एंट्री नंबर 4 जी में आग लग गई। यहां सोफा बनाने का काम होता है। आग लगने की सूचना पर तकाल स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंची।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीता 2 इलाकों में एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग बुझाने के बाद अंदर चालते अपरेशन चलाया गया। इस दौरान यहीं चाल चली अंदर गंभीर हालत में मिले। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और आग लगने के दौरान यहां मौजूद थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 नवंबर को थाना बीता 2 थंक्रे के अंतर्गत साइट फॉर एंट्री नंबर 4 जी में आग लग गई। यहां सोफा बनाने का काम होता है। आग लगने की सूचना पर तकाल स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंची।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीता 2 इलाकों में एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग बुझाने के बाद अंदर चालते अपरेशन चलाया गया। इस दौरान यहीं चाल चली अंदर गंभीर हालत में मिले। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और आग लगने के दौरान यहां मौजूद थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 नवंबर को थाना बीता 2 थंक्रे के अंतर्गत साइट फॉर एंट्री नंबर 4 जी में आग लग गई। यहां सोफा बनाने का काम होता है। आग लगने की सूचना पर तकाल स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंची।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीता 2 इलाकों में एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग बुझाने के बाद अंदर चालते अपरेशन चलाया गया। इस दौरान यहीं चाल चली अंदर गंभीर हालत में मिले। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और आग लगने के दौरान यहां मौजूद थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 नवंबर को थाना बीता 2 थंक्रे के अंतर्गत साइट फॉर एंट्री नंबर 4 जी में आग लग गई। यहां सोफा बनाने का काम होता है। आग लगने की सूचना पर तकाल स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंची।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीता 2 इलाकों में एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग बुझाने के बाद अंदर चालते अपरेशन चलाया गया। इस दौरान यहीं चाल चली अंदर गंभीर हालत में मिले। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और आग लगने के द





# संपादकीय

---

## कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

देश के कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनी को अवश्य ही दर्दित किया जाना चाहिए। बहरहाल, ऐसे कदम उठाते समय जांच एजेंसियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ना सिर्फ निष्पक्ष रहें, बल्कि निष्पक्ष दिखें भी। ई-कॉर्मर्स क्षेत्र की फिलपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने भारतीय कानून को तोड़ा हो, तो बेशक उन पर प्रावधान के अनुरूप सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों अमेरिकी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं (फिलपकार्ट में लगभग तीन चौथाई हिस्सा बॉलमार्ट का है)। भारत के ई-कॉर्मर्स बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा उनके पास ही है। एक अनुमान के मुताबिक 70 बिलियन डॉलर के इस बाजार में फिलपकार्ट का हिस्सा 32 और अमेजन का 24 फीसदी है। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इनके विक्रेताओं पर छापा मारा। उसके बाद इन कंपनियों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने विदेशी निवेश संबंधी कानून का उल्लंघन किया। इस कानून के तहत विदेशी ई-कॉर्मर्स कंपनियों विक्रेताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं। साथ ही ये विक्रेताओं से सामान खरीद कर अपना भंडार नहीं बना सकतीं। अमेजन और फिलपकार्ट का कहना है कि उहोंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। मगर ईडी का दावा है कि उसके पास इन कंपनियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। निविंवाद है कि हर कंपनी- चाहे वो देशी हो या विदेशी- उसे सख्ती से देश के कानून का पालन करना चाहिए। कोई कंपनी ऐसा नहीं करती, तो उसे अवश्य ही दर्दित किया जाना चाहिए। बहरहाल, जांच एजेंसियों को ऐसे कदम उठाते समय यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ना सिर्फ निष्पक्ष हों, बल्कि निष्पक्ष दिखें भी। इस संदर्भ में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरे वर्षों में ऐसी धारणा (जो संभव है कि निराधार हो) बनी है कि भारत सरकार के कृष्ण पसंदीदा उद्योग घराने हैं और जब उनके हित किसी विदेशी (या देशी) कंपनी से टकराते हैं, तो जांच एजेंसियां अति सक्रिय हो जाती हैं। अतीत में वर्तमान सरकार से ही जुड़े रहे कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस धारणा को भारत में विदेशी निवेश के रास्ते में मौजूदा रुकावटों में एक बताया है। यह समय अंतरराष्ट्रीय कागोबार के लिए प्रतिकूल है। इस वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। इस हाल में उपरोक्त धारणा को तोड़ना अत्यधिक अवश्यक हो गया है। आशा है, ईडी इस अपेक्षा के प्रति जागरूक होगा।

# सर्वोच्च न्यायालय जनता की अदालत है

ओमप्रकाश मेहता

भारत की न्याय पालिका हमारे संविधान की मंशा के अनुरूप ही काम कर रही है तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका जैस नहीं है, जहां मामले देशकों तक लम्बित रहते हैं, हमारी ओर से दिन में जितने मामलों का निराकरण होता है उतने तो कई पश्चिमी देशों में एक वर्ष में भी नहीं दिया जाताये उद्घार भारत की न्याय व्यवस्था व न्याय में कथित विलम्ब के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने व्यक्त किए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जनता की अदालत है और उसे अपनी इस भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कानून के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने न्याय पालिका से उस पर पक्षपात व न्याय संहिता के विपरीत काम करने के आरोपों पर अपना मन्तव्य व्यक्त किया। उन्होंने न्याय पालिका की प्रजतांत्र में अहम् भूमिका भी प्रतिपादित की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्याय पालिका को स्पष्ट हिदायत दी कि उसे देश के सामने प्रतिपक्षी दल की भूमिका में कर्तई सामने नहीं आना है, क्योंकि न्याय पालिका ही वर्तमान प्रजातंत्र के तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में आज विश्वसनीय रही है तथा देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र के इसी अंग के प्रति विश्वास व निष्ठा शेष बची है। माननीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के इस दावे की सच्ची व ईमानदारी समीक्षा तो जनता के स्तर पर होगी, किंतु इसी बीच यह आरोप भी सच है कि देश की विभिन्न अदालतों में कई वर्षों से करोड़ों मामले लम्बित हैं इन अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, यहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों के निराकरण

को शीघ्र व निश्चित समयसीमा में करने को सही तो बताया था लेकिन इसे असंभव भी करार दिया था, क्योंकि उनका सरकार पर स्पष्ट आरोप था कि करोड़ों लम्बित मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं कर पा रही है, यदि पर्याप्त अदालतें, न्यायाधीश व अमला हो तो लम्बित मामले शीघ्र ही निपटाए जा सकते हैं। न्याय पालिका के इस जवाब पर केन्द्र सरकार पूरी तरह मौन है। अब यह समझ से परे है कि सरकार की इस मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं है? यहां यह विचारणीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार पर पूरा ठीकरा फोड़ने के बजाए स्वयं उसे ही अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्च न्यायालयों से लेकर जिला स्तर तक की अदालतों के लिए मार्गदर्शक बिन्दू है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इस दिशा में आदर्श स्थापित करना चाहिए, फिर उसी का अनुसरण निचली अदालतें भी करेगी। फिर वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा करने वालों को आशा की कोई किरण नजर आएगी। किंतु अब फिर वही सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह कहने को क्यों बाध्य होना पड़ा, कि %सुप्रीम कोर्ट को प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं, उनका कहना था कि %क्या यह किसी से भी छिपा है कि पिछले कुछ समय से सरकार के हर फैसले और यहां तक कि संसद से पारित प्रत्येक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौति देने का सिलसिला निकल पड़ा है? यदि सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं के सहारे सरकार एवं संसद के हर फैसले की समीक्षा करेगा और यहां तक की कानूनों की वैधानिकता को परखे बिना उसके अमल पर रोक लगा देगा, जैसा कि कृषि कानूनों के बारे में हुआ था, तो फिर तो वह विपक्ष की भूमिका में ही नजर आएगा? यदि सर्वोच्च न्यायालय को जनता की अदालत के रूप में अपनी छवि को मजबूत करना है तो उसे संसद के हर फैसले की समीक्षा करना छोड़ा होगा और देश की जनता को तय समय पर शीघ्र व सस्ता न्याय देने की पहल करनी होगी, यही प्रजातंत्र की अपने इस अंग से अपेक्षा है।

1

गरीब कल्याण और समाज के निचले तबके के लिए समृद्धि का रास्ता खोलने में सहकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। डेयरी, खाद और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की सफलता के बाद अब बारी अन्य क्षेत्रों की है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय तथा सरकारी बित्तियां भी बनाईं हैं।

का गठन भा क्या ह। बीते तीन वर्ष में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। संभवत् यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) को वैश्विक सहकारी सम्मेलन कराने के लिए इस वर्ष भारत आना पड़ा। सहकारिता के बढ़ते महत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकारा है, और 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नई दिल्ली में 25 नवम्बर से होने वाला वैश्विक सहकारी सम्मेलन-2024 दुनिया भर के सहकारिता क्षेत्र में भारत की

# सहकारिता की भूमिका वेद महत्वपूर्ण

स्थिति को और मजबूत करेगा। आईसीए की स्थापना (1895) के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह आयोजन भारत में होने जा रहा है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। आईसीए सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष वैश्विक संस्था है, जिसकी संख्या दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा है। विश्व में 107 देशों के 310 से अधिक संगठन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सदस्य हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी की बांगड़ेर विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको समेत देश की 17 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के हाथों में है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह सम्मेलन सहकार से समृद्धि के भारत के संकल्प को पूरी दुनिया में ले जाएगा। आईसीए ने भी इस सम्मेलन का थीम %सहकारिताएं-सबकी समृद्धि का द्वार' तय किया है। इस सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने 'हाट' में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सम्मेलन के दौरान 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने की औपचारिक घोषणा और इस विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करें। मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष में दर्जनों महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे नई ऊँचाइयों पर पहुंचा दिया है। सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए नये मंत्रालय का भी गठन किया गया। सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के पुनर्गठन और निष्क्रिय हो चुकीं प्राथमिक सोसाइटियों को पुनर्जीवित किया गया है। मॉडल बायलॉज से प्राथमिक कृषि त्रया सोसाइटी (पैक्स) को ताकत दी गई और उनके कामकाज के दायरे को बढ़ाया गया। सहकारिता पर लागू टैक्स को तर्क संगत बनाया गया। दुनिया में लगभग 30 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें से करीब 8 लाख सहकारी समितियां यानी एक चौथाई से अधिक समितियां भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक लोग इन समितियों के

स्य हैं, जिनमें से 29 करोड़ से ज्यादा स्थ भारत के हैं। सहकारिता क्षेत्र ने या भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों रोजगार दिया है। सहकारी समितियों की संख्या और के विस्तार की संभावनाओं के मामले पारत का इतिहास गैरवशाली रहा है। तीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा वर्तन पैक्स के मॉडल बायलॉज का अन्वन्यन है। सहकारिता क्षेत्र में तीन नई य बहुराजीय सहकारी समितियों- य सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल), राष्ट्रीय सहकारी नियंत्रित मटेड (एनसीईएल) और भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड (बीएसएसएल) के गठन ने भारत को एक सहकारिता आंदोलन में अग्रणी दिया है। इन पहल ने दूसरे देशों का न खंचा है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के न जहां संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से पूरा करने रूपरेखा तैयार की जाएगी, वहीं

# उदास लोगों का देश बनना भारत की एक ग्रासदी

ललित गग्नी

भारत उदास, निराश एवं थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। हम प्रसन्न समाजों की सूची में अब्बल नहीं आ पा रहे हैं। आज अवसर लोग थके हुए, उदास, निराश नज़र आते हैं, बहुत से लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम करने में ही थक जाते हैं। उनका कुछ करने का ही मन नहीं होता। छोटे-मोटे काम भी थकाऊ और उबाऊ लगते हैं। विडम्बना तो यह है कि लम्बे विश्राम एवं लम्बी छुट्टियों के बाद भी हम खुद को तरोताजा नहीं बना पा रहे हैं। भारत में ऐसे लोगों का प्रतिशत लगभग 48 तक पहुंच गया है, जो चिन्ना का बड़ा सबब है। ऐसे थके एवं निराश लोगों के बल पर हम कैसे विकसित भारत एवं नये भारत का सपना साकार कर पायेंगे? यह सवाल सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन करने का अवसर दे रहा है, वहाँ नीति-निर्माताओं को भी सोचना होगा कि कहाँ समाज निर्माण में त्रुटि हो रही है कि हम लगातार थके हुए लोगों के देश के रूप में पहचाने जा रहे हैं। खुशहाल देशों की सूची में भी हम सम्पान्नजनक स्थान नहीं बना पा रहे हैं।



भारत इस वर्ष 143 देशों में 126वें स्थान पर है। यह ऐक पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल वही रही है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन 60वें, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। जीवन की सकारात्मकता एवं विकास की दशा है। यही हमारी अराजक उपचारों का फल है। कुछ ऐसे रोगों का इलाज कर सकती है। कुछ ऐसे रोगों का इलाज कर सकती है। माने जाते, उन पर अंकुश लगाया जाए। अपने घर में आहार-विहार का नियम लगाया जाए।

वैं जीवन-ऊर्जा समाहित नीतीवन शैली को संयमित रखा जो उपचार योग्य नहीं लगा सकती है। व्यक्ति को संतुलित करके भी प्रयोग कर सकता है। हम हालातों में इंसान कैसे खुशहाल, जोशीला एवं सकारात्मक जीवन जी सकता है? इन गहन अंधेरों से बाहर निकलते हुए विगत एक दशक में सरकारों के कामकाज एवं नीतियों से एक आशावाद झलका है, लेकिन इंसानों का लगातार निराश एवं उदास होते जाना एक बड़ी चुनौती है।

वैसे भी खुशी, जोश एवं उत्साह महसूस करना व्यक्ति के खुद की सोच पर निर्भर करता है। इसलिये

बढ़ जाती है। आमतौर से जनवरी तक सूर्य स्नान टामिन-डी मिल जाता है। श्रम नहीं करते। खान-मिलावट है। बाजार की फैलती हैं। पारिवारिक गारा है, कॉरपोरेट संस्कृति हाली बहुत पीछे छूट रही धुनिक रोग काम न करने दिमाग को थका रहे हैं, हैं। इसी वजह से शरीर अदमी पैदल नहीं चल रहा और भूरी है हम आहार सही नहीं। आहार दवा है। देर रात जगना एवं सुबह देर से चार करने जैसा है। इन्हीं स्थितियों ने हमें उदासी दी कावट, दुख या खुशी एक र जिसी सर्वे के जरिये आ। फिर भी, ऐसी सूचियों प्रश्न है कि हमारी जोश, तरोताजगी एवं उत्साह का पैमाना क्या हो? विकास की सार्थकता इस बात में है कि देश का आम नागरिक खुद को संतुष्ट, जोशीला, तरोताज और आशावान महसूस करे। स्वयं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बने, कम-से-कम कानूनी एवं प्रशासनिक औपचारिकताओं का सामना करना पड़े, तभी वह निराशा एवं उदासी को कम कर पायेगा। कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिलीकरण, आर्थिक नवाचार जैसी घटनाओं ने आम आदमी को अधिक परेशानी एवं कंकाली दी है। समस्याओं के बनघोर अंधेरों के बीच उनका चेहरा बुझा-बुझा है। न कुछ उनमें जोश है न होश। अपने ही विचारों में खोए-खोए, निष्क्रिय और खाली-खाली से, निराश और नकारात्मक तथा ऊर्जा विहीन। हाँ सचमुच ऐसे लोग पूरी नींद लेने के बावजूद सुबह उठने पर खुद को थका महसूस करते हैं, काये के प्रति उनमें उत्साह नहीं होता। ऊर्जा का स्तर उनमें गिरावट पर होता है। क्यों होता है ऐसा? कभी महसूस किया आपने? यह स्थितियां एक असंतुलित एवं अराजक समाज व्यवस्था की निष्पत्ति है।

# आतंकवाद पर रुख स्पष्ट करे सियासत

प्रताप सिंह पटियाल

‘सेवा अस्माकं धर्मः’, अर्थात् ‘राष्ट्र की सेवा हमारा धर्म है।’ यह प्रसंग भारतीय थलसेना का आदर्श वाक्य है। सेना के लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि रहा है। इसीलिए देश सुरक्षित है। मगर देश पर हुक्मरानी करने वाले सियासी निजाम के लिए बोट बैंक व सत्ता सर्वोपरि होती है। इस नवंबर महीने में वीरभूमि हिमाचल के हिस्से दो और सैन्य बलिदानों का इजाफ हो गया। जम्मू कश्मीर के किशतवाड़ में सेना की ‘दो पैरा स्पेशल फोर्स’ के जेसीओ राकेश कुमार दस नवंबर 2024 को आर्टिकियों से लड़ते बलिदान हो गए। 13 नवंबर को हवलदार सुरेश कुमार ‘डोगरा रेजिमेंट’ लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वीरगति को प्राप्त हो गए। राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की सैन्य परंपरा को निभाने वाले दोनों सपूत्रों का संबंध मंडी जिला से था। डोगरा शासकों के समय से लेकर मौजूदा दौर तक जम्मू कश्मीर के लिए हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों की दास्तान-ए-सुजात की फेरहिस्त काफी लंबी है। जम्मू कश्मीर रियासत के जरनैल ‘जोरावर सिंह कहलूरिया’ ने डोगरा सल्लनत की सरहदों को अफानिस्तान से लेकर तिब्बत के महाज तक विस्तार देकर लद्दाख के रणक्षेत्र में अपना बलिदान दिया था।

कट्टन सजय चाहान शाय चक्र, पवन धगल  
 'कीर्ति चक्र', कुलभूषण मांटा 'शौर्य चक्र' तथा  
 सूबेदार संजीव कुमार 'कीर्ति चक्र' जैसे हिमाचल  
 के सैंकड़ों बहादुर सैनिकों ने कश्मीर की सुरक्षा के

लिए आतंकवाद से लड़कर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। लेकिन देश की फिजाओं में हरदम सियासी माहौल रहता है। सियासी हुक्मरान देश का राष्ट्रीय खेल बन चुकी सियासत में शशगूल रहते हैं। सियासत जाति, मजहब व वंशवाद की तवाफकरती है। मुल्क का भीड़िया सियासत की तवाफकरता है। नतीजतन फिर-ए-वतन हो रहे जांबाजों का सर्वोच्च बलिदान कभी न्यूज चैनलों की सुखियां नहीं बनता। युवा वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत हमारा गौरवशाली सैन्य इतिहास कभी शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना। सैनिकों की रक्तरंजित शूरवीरता पर मायानगरी के अदाकार फिल्में बनाकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, मगर वतन-ए-अजीज की हशमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले वास्तविक नायक गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक मुद्दत से चुनौती बन चुका है। मुल्क के नीति-निर्माताओं के गलत फैसलों का खामियाजा सैनिक व सैन्य परिवार भुगत रहे हैं। कश्मीर हथियाने के लिए चार बड़े युद्धों में मिली शर्मनाक शिक्षस्त के बदनुमां दाग मिटाने के लिए पाक सेना ने भारत के खिलाफ आतंक को अपना हथियार बनाया। मजहबी रहनुमाओं की जहरीली तालीम ने युवाओं को जनत में बहतर हूरों का जहालत भरा ख्वाब दिखाकर उनके जहन में मजहबी जिहाद का मवाद भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। पाक परस्त दहशतगर्दों को कश्मीर की स्थानीय आबादी व सियासत की परी हिमायत हासिल हई। बिना लोकल स्पोर्ट के

आतंकवाद, अलगाववाद व चरमपंथ कभी पैर न पसार सकते। इसी पाक परस्त आतंक के कारण 1990 के दशक में कश्मीर के मूल निवासी लाखों बेगुनाह लोग घाटी से हिजरत करके अपने ही मुलायम शरणार्थी बन गए।

लेकिन आतंक व पलायन के उस खौफनाम जंर पर भी कश्मीर से लेकर मरकजी हुक्मत त देश की सियासत मौन थी। मुफ्तखोरी की खँैरात जरिए मुल्क की हर सियासी जमात सत्ता के फल पर विराजमान होने को बेताब रहती है। आतंकवाद का मसला तथा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुझम्हरियत की पंचायतों में कभी चर्चा का मरक नहीं बना। जम्मू कश्मीर रियासत के हुक्मरान ह सिंह की रियासती सेना सन् 1947 में पाक सेना हमले को रोकने में विफल रही थी। उस व भारतीय सेना ने जोरदार पलटवार करके कश्मीर व बचाया था। पाक परस्त आतंक से निपटने में जायक कश्मीर राज्य की पुलिस फेर्स भी नाकाम रही त नतीजतन 'राष्ट्रीय राइफल्स' की साठ से अधिक बटालियन घाटी में तैनात करनी पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान से सटी जम्मू-कश्मीर व सरहदों पर सेना के सात डिवीजन तैनात हैं। बेतुवा बयानबाजी से अपनी सियासी जमीन मजबूत करावाले कश्मीर के सियासी रहनुमा खुद सेना व सर्वश्रेष्ठ सिक्योरिटी के दायरे में महफूज रहते हैं। राज्य की पुलिस फेर्स अपने अधिकारियों व प्रशासन तथा सियासतदानों की सुरक्षा में मशरूफ है। घाटी काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की टारंग कीलिंग हो रही है। 'ग्राम सरक्षा गार्डों' का अपहरण

# महत्वपूर्ण

रोड़ से ज्यादा गरिता क्षेत्र ने ज्यादा लोगों संख्या और अंतों के मामले शाली रहा है। वैधुति में सबसे बड़ा बायलॉज का नेत्र में तीन नई विधियों का लिमिटेड हकारी नियांत्रण और भारतीय न न लिमिटेड ने भारत को न में अग्रणी दूसरे देशों का सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन में इन सभी लक्ष्यों पर व्यापक चर्चा भी कराई जाएगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही वैश्विक चिंताओं को दूर करने को लेकर तैयार बिंदुओं पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य चिन्हित किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सहकारी समितियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इनमें पारिस्थितिकी संतुलन, स्थिर आजीविका, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास एवं सहयोग, मिट्टी की सेहत एवं जीवन, महिला सशक्तिकरण सहित प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार आदि विषयों को शामिल किया गया है। सहकारिता वर्ष मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक

वर्ष 2025 के निर्धारित लक्ष्य से पूरा करने जाएगी, वहाँ की समयावधि निर्धारित की गई है। इसमें सहकारी क्षेत्र की भूमिका पहले ही निर्धारित कर दी गई है, जिससे सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ गया है।







